राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 03 जून 2026
वर्ष 14, अंक 54, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

मलिहाबाद के घुसौली गांव में नालियों का पानी सड़क पर, डेढ़ साल से ग्रामीण परेशान, प्रदर्शन की चेतावनी...03

ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय में उपस्थिति एवं फोन चालू रखने के आदेश पर शिक्षकों में रोष...04

भरोसा, पावर और कद क्या अन्नामलाई की BJP हाईकमान से बनी बात

तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी के तीन शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई नेताओं से अन्नामलाई मिले. माना जा रहा है कि पार्टी हाई कमान से मुलाकात के बाद अब अन्नामलाई की नाराजगी दूर हो गई. खुद बीजेपी हाई कमान भी ये मानकर चल रहा है. हालांकि अभी भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है. अन्नामलाई ने सबसे पहले आज सुबह संगठन महामंत्री बी एल संतोष से मुलाकात की. इसके बाद अन्नामलाई ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और अंत में दोपहर करीब 2:00 बजे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर अपनी बातें रखी. हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी शीर्ष नेताओं के साथ अन्नामलाई की मुलाकात में क्या बात हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इस मुलाकात को अन्नामलाई की नाराजगी और अलग रास्ता अख्तियार करने से जोड़ कर देखा जा रहा है.

बेहतरीन इस्तेमाल करने का आश्वासन

पार्टी सूत्रों का कहना है की शीर्ष नेताओं से मुलाकात के दौरान के अन्नामलाई ने भाजपा नेतृत्व से अपनी नाराजगी की वजह और तमिलनाडु के मौजूदा राजनीतिक हालात में बने वेक्यूम का जिक्र किया. साथ ही तमिलनाडु की मौजूदा राजनीतिक हालात पर विस्तृत चर्चा भी की. सूत्रों का यह भी कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने अन्नामलाई ने अपनी सारी शिकायतें रखते हुए विस्तार से अपनी बात रखी. दोनों ही नेताओं ने अन्नामलाई को भविष्य में उनके रोल और कद को बढ़ाने और उनके कार्य क्षमता का बेहतरीन इस्तेमाल करने का आश्वासन दिया.

भाजपा नेतृत्व ने अन्नामलाई को दिलाया भरोसा

पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व ने अन्नामलाई को भरोसा दिलाया कि उन्हें जल्द ही पार्टी उनकी क्षमता के अनुसार उचित स्थान देगी. हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है की अन्नामलाई ने अपना इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने पेश किया लेकिन पार्टी इस पर कुछ भी कहने से बचती रही. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के साथ अन्नामलाई की मुलाकात और उसके बाद दोनों की तस्वीर को सार्वजनिक तौर पर साझा करना यह दिखाता है की स्थिति सामान्य है. चर्चा इस बात की भी है की अन्नामलाई को लेकर बीजेपी एक दीर्घकालिक रणनीति बनाते हुए सूबे की राजनीति में एक नया प्रयोग कर सकती है.

क्या मानते हैं अन्नामलाई समर्थक?

अन्नामलाई समर्थकों का मानना कि तमिलनाडु में जोसेफ विजय की पार्टी के सत्ता में आने के साथ ही यह स्पष्ट है की डीएमके समर्थक वोट अब ज्यादा टीवीके के पास जा रहा है. वही एआईडीएमके समर्थकों में निराशा का भाव है और एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर उस स्पेस को बीजेपी भर सकती है. इसलिए अन्नामलाई तमिलनाडु में यात्रा कर एग्रेसिव ढंग से राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

बीजेपी का तमिलनाडु में प्रदर्शन

जानकारी के मुताबिक अन्नामलाई इस बात को अपनी पक्ष में रख रहे हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2.5% से भी कम वोट हासिल कर पाई थी. जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में उनके एग्रेसिव कैंपेन और एआईएडीएमके से अलग होकर चलने के चलते बीजेपी को भले ही मन मुताबिक सीट हासिल नहीं हुई लेकिन 10.53 प्रतिशत वोट जरूर मिला जो फिर 2026 विधानसभा चुनाव में घटकर 3% से भी कम रह गया है. लिहाजा भाजपा एआईएडीएमके से अलग होकर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.

पार्टी के अगले आदेश का इंतजार

बहरहाल के अन्नामलाई दिल्ली में ही मौजूद हैं और पार्टी के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं. अन्नामलाई से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हो सकती है. इस बीच तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायनार नागेंद्रन को दिल्ली बुलाया गया है.

शादीशुदा बेटी भी रोजगार की पात्र... अनुकंपा नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता पर आश्रित विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के पात्र माना है. एससी ने फैसले में कहा है कि माता-पिता के ना रहने पर उनपर आश्रित विवाहित पुत्री अनुकंपा रोजगार की पात्र है. अगर विवाहिता बेटी रोजगार संबंधी सभी शर्तों को पूरा करती हैं तो उन्हें नियुक्ति के पात्र माना जाएगा. इससे पहले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित पुत्री को शामिल नहीं किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को रद्द किया है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट के उन सभी निर्णयों से सहमत है, जिनमें कहा गया है कि वैवाहिक स्थिति किसी पात्र पुत्री को कल्याणकारी योजना से वंचित करने का वैध आधार नहीं हो सकती. यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच द्वारा सर्वोच्च अदालत को भेजे गए एक संदर्भ से संबंधित है, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या विवाहित पुत्रों के मामले में ऐसी कोई अक्षमता न होने पर भी विवाहित पुत्रियों के अनुकंपा नियुक्ति के दावों को अस्वीकार किया जा सकता है.

दुकान चलाने के लाइसेंस के लिए याचिका की थी दायर

इस मामले में याचिकाकर्ता, जो एक विवाहित पुत्री है. उसने अनुकंपा के आधार पर उचित दुकान चलाने के लाइसेंस के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें 2019 के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें विवाहित पुत्रियों को 'परिवार' की परिभाषा से बाहर रखा गया था. दरअसल विवाहित होने के बावजूद वह अपने परिवार के साथ रहती थी. एक विकलांग बहन की देखभाल करती थी और अपनी मां के साथ दुकान चलाती थी. अपनी मां के निधन के बाद याचिकाकर्ता ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया.

पहले के कुछ निर्णयों पर किया गया विचार

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अदालत के समक्ष मौजूद पूर्व निर्णयों पर विचार किया. उन्होंने विमल श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015) मामले में खंडपीठ के फैसले पर गौर किया, जिसमें सेवा संबंधी मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 'परिवार' की परिभाषा से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974 के एक समान प्रावधान की व्याख्या करते हुए यह माना गया था कि विवाहित बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखना असंवैधानिक है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है और इस प्रकार परिवार की परिभाषा में प्रयुक्त 'अविवाहित' शब्द को निरस्त कर दिया गया था. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के समक्ष कुसुमलता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2021) मामले में विवाहित पुत्री द्वारा चुनौती दिए गए दावे पर 2019 के सरकारी आदेश पर भी विचार किया गया. इसमें यह माना गया कि विमल फैसले का तर्क लागू नहीं किया जा सकता. इसमें यह भी कहा गया कि 2019 के सरकारी आदेश में परिवार की परिभाषा में 'अविवाहित पुत्री' शब्द का प्रयोग भेदभावपूर्ण नहीं है. इसमें यह भी माना गया कि 2019 के सरकारी आदेश की व्याख्या उस तरह से नहीं की जा सकती जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हार्नेस नियमों के प्रावधानों की व्याख्या की थी. इसी तरह का मत सैदा बेगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2023) मामले में खंडपीठ द्वारा भी व्यक्त किया गया था. न्यायाधीश ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने रंजना मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के विपरीत निर्णयों को रद्द कर दिया.

चार सप्ताह के भीतर वैध लाइसेंस देने का आदेश

आज सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैदा बेगम का मामला सही कानूनी आधार नहीं है. इस मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता विवाह के बाद भी उसी गांव में रहती रही और उचित मूल्य की दुकान चलाने में अपनी मां की सक्रिय रूप से सहायता करती रही. अपनी मां के निधन के बाद अपीलकर्ता ने अपनी बहन, जो शारीरिक रूप से अक्षम थीं, उनकी जिम्मेदारी संभाली. विवाहित पुत्री होने के आधार पर उसका आवेदन खारिज करना संवैधानिक रूप से अमान्य है. सुप्रीम कोर्ट ने उसे लाइसेंस देने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द कर दिया और सक्षम अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर वैध लाइसेंस आदेश जारी करने का निर्देश दिया.

संक्षिप्त ख़बरें

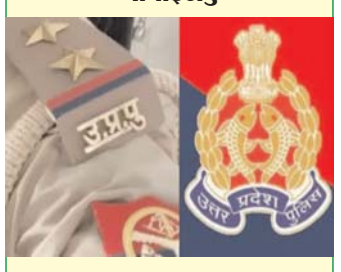

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नहीं उतरेंगे कलवा और मंगलसूत्र, टीचर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइलड्

उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. 8, 9 और 10 जून को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए ग्रेटर नोएडा में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर करीब 42 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को जांच के दौरान कलावा और मंगलसूत्र उतारने की अनिवार्यता नहीं होगी. वहीं, स्मार्ट गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन और अन्य संदिग्ध उपकरणों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

कैसे होगी निगरानी?

इस बार परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस मिलान और लाइव सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की व्यवस्था रहेगी. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा एजेंसियां और अधिकारी अलर्ट रहेंगे. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. वहीं, अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा, ताकि जांच प्रक्रिया समय से पूरी हो सके.

मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे टीचर

सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा ड्यूटी में तैनात शिक्षक और कर्मचारी केंद्र के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे. परीक्षा के दौरान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाएगी. जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने की तैयारी की गई है. परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और शिक्षक केंद्र के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जाएगी.

सूर्या हत्याकांड के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, खोड़ा में 3 मदरसे सील, PAC-RAF तैनात

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गाजियाबाद जिले के खोड़ा इलाके में सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है. 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के तहत तीन दिनों से इलाके में हिस्ट्रीशीटरों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस टीमें चिन्हित अपराधियों के घरों पर दबिश दे रही हैं, जबकि संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर उनका सत्यापन भी किया जा रहा है. वहीं मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खोड़ा के तीन मदरसों को सील कर दिया. इस दौरान भारी संख्या में PAC और RAF के जवान तैनात रहे.

ड्रोन कैमरों से की जा रही निगरानी

डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ का कहना है कि इलाके में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है. निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन कैमरों, स्निफर डॉग्स और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है. संवेदनशील इलाकों और कई मकानों की छतों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके. बता दें कि यह अभियान सूर्या हत्याकांड के बाद शुरू किया गया है. मामले के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया गया था.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में डर पैदा करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा.

मदरसों पर नोटिस चस्पा किया गया

डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बताया कि इलाके में जो भी अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है. करीब तीन ऐसे मदरसों को चिन्हित किया गया है, जो अवैध रूप से चल रहे हैं. उन पर कार्रवाई की गई है. उन्हें सील किया गया है और बाकायदा नोटिस चस्पा कर जवाब एक हफ्ते के अंदर मांगा गया है. अवैध मदरसा इसलिए था, क्योंकि इसका पंजीकरण नहीं था, न ही अल्पसंख्यक बोर्ड में रजिस्टर था. प्रशासन कहना है कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह का 'ऑपरेशन क्लीन' लगातार चलाया जाएगा. बता दें कि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस ऑपरेशन को तीन मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है. पहला, डोर-टू-डोर जाकर अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन करना. दूसरा, अपराध से जुड़े लोगों को थाने बुलाकर उन्हें चेतावनी देना और तीसरा, सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों की जांच कर कार्रवाई करना. अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के साथ-साथ अवैध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाना है.

भारी संख्या में PAC और RAF के जवान तैनात

खोड़ा क्षेत्र में सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल के साथ PAC और RAF को भी मौके पर बुलाया गया है. प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाले जाने की तैयारी की गई है. अधिकारियों का मानना है कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी से कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी.

दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर ब्लास्ट, जोरदार धमाके से ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान, मलबे में दबे कई लोग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी स्थित मुकुंदपुर इलाके में मंगलवार सुबह एक भीषण और दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां एक रिहायशी मकान में तेज धमाके के साथ एलपीजी (LPG) सिलेंडर फट गया, जिसके बाद पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई. धमाका इतना जोरदार था कि पल भर में ही मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया. इस हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की 5 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. फिलहाल युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य (रेस्क्यू ऑपरेशन) जारी है. स्थानीय निवासियों और शुरुआती जांच से मिली जानकारी के अनुसार, जिस मकान में यह ब्लास्ट हुआ है, वहां अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का कारोबार किया जा रहा था. इस जगह पर अवैध तरीके से सिलेंडर भरकर सप्लाई करने का काम होता था. इसके अलावा, इसी परिसर में बर्तनों की रंगाई, पाउच बनाने और मोबाइल चार्जर की अवैध फैक्ट्री भी संचालित हो रही थी. रिहायशी इलाके में इस तरह के कमर्शियल और जोखिम भरे काम होने की वजह से ही यह बड़ा हादसा हुआ, जिसने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है.

सुबह 9:27 बजे दमकल को मिली सूचना, 6 लोगों का रेस्क्यू

फायर विभाग के मुताबिक, उन्हें सुबह करीब 9 बजकर 27 मिनट पर मुकुंदपुर इलाके में ब्लास्ट और मकान गिरने की कॉल मिली थी. मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक-एक कर दमकल की 5 गाड़ियों को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया. राहत और बचाव टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे को हटाने का काम तुरंत शुरू किया. अब तक मलबे के नीचे दबे 6 लोगों को बेहद जख्मी और गंभीर हालत में बाहर निकाला जा चुका है. सभी घायलों को तुरंत पास के नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है. हालांकि, घायलों की स्थिति अभी कैसी है, इस पर आधिकारिक बयान आना बाकी है.

मलबे में अन्य लोगों की तलाश जारी

हादसे के बाद पूरे मुकुंदपुर इलाके में अफरा-तफरी और चीख-पुकार का माहौल है. आसपास के लोगों का कहना है कि इमारत के अंदर कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिनके मलबे में दबे होने की पूरी आशंका है. दमकल कर्मी और पुलिस की टीमें कंक्रीट और मलबे के भारी टुकड़ों को हटाकर बेहद सावधानी से अंदर फंसे अन्य लोगों की तलाश कर रही हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.

100 की चोरी, पुलिस हिरासत में मौत और 29 साल बाद फैसला 3 आरोपी दोषी करार, कहानी राजेंद्र सिंह केस की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

वाराणसी की स्पेशल कोर्ट ने 29 साल पुराने चर्चित राजेंद्र सिंह हिरासत मृत्यु मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) अमित कुमार तिवारी की अदालत ने तत्कालीन सुंदरपुर चौकी इंचार्ज नरेंद्र सिंह, एक डॉक्टर और एक रिटायर्ड दरोगा को दोषी करार दिया है. अदालत ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज नरेंद्र सिंह को 10 साल, संदिग्ध पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर के.के. जैन को 5 साल और तत्कालीन दरोगा राधेश्याम को 6 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही नरेंद्र सिंह पर 31 हजार और डॉक्टर केके जैन पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. ये 40 साल में पहली बार है, जब पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले में ऐसी सजा सुनाई गई है.

5 फरवरी 1997 की वह सुबह, जिसने बदल दी पूरी जिंदगी

वाराणसी जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित बखरिया गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह अपनी पत्नी शशिमा देवी और परिवार के साथ रहते थे. खेती और निजी नौकरी के सहारे वह परिवार का पालन-पोषण करते थे. जनवरी 1997 में उनके घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ था. 5 फरवरी की सुबह राजेंद्र सिंह अपने नवजात बेटे के लिए दवा लेने घर से निकले थे. रास्ते में महानगरी बस में एक सहयात्री से सीट को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर सहयात्री ने उन पर 100 रुपए चोरी करने का आरोप लगा दिया. मामला सुंदरपुर चौकी तक पहुंचा और वहां तत्कालीन चौकी प्रभारी नरेंद्र सिंह और सब-इंस्पेक्टर राधेश्याम सिंह ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

हिरासत के कुछ घंटों बाद आई मौत की खबर

परिवार के अनुसार, कुछ देर बाद चौकी से सूचना दी गई कि राजेंद्र सिंह को छोड़ दिया गया है, लेकिन बाद में पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने अपने शॉल से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. राजेंद्र सिंह की पत्नी शशिमा देवी ने आरोप लगाया कि यह कहानी शुरू से संदिग्ध थी. उनका कहना है कि चौकी में पंखा तक नहीं था, फिर फांसी की बात कैसे सामने आई. परिवार का आरोप है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी गलत तथ्य दर्ज किए गए. शशिमा देवी का आरोप है कि उन्हें अपने पति का अंतिम चेहरा तक देखने का मौका नहीं दिया गया और पुलिस अंतिम संस्कार कर लौट रही थी.

29 साल की लड़ाई में परिवार ने सब कुछ खो दिया

शशिमा देवी ने हार नहीं मानी और मामले को मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाया. बाद में जांच सीबी-सीआईडी (अब CBI) को सौंपी गई. उनका कहना है कि न्याय की इस लंबी लड़ाई में परिवार ने अपनी जमीन, खेत और आर्थिक स्थिरता सब कुछ खो दिया. बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हुई. शशिमा देवी कहती हैं, 29 साल बाद कोर्ट ने हमारी बात को सही माना है, लेकिन क्या इसे पूरा न्याय कहा जा सकता है? मेरा सब कुछ चला गया. आज भी पांच किलो राशन और बच्चों की कमाई के सहारे जिंदगी चल रही है.

फैसले से मिली राहत, लेकिन सवाल अब भी बाकी

करीब तीन दशक बाद आए इस फैसले ने परिवार को कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि संघर्ष, दर्द और इंतजार की कहानी भी है. अब भी परिवार मानता है कि न्याय की लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

पेपर लीक के आरोपी यश यादव ने कहा-मुझे 21 जून को नीट का एग्जाम देना है, तैयारी के लिए बुक चाहिए

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

NEET-UG पेपर लीक मामले में आरोपी मंगिलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे को मंगलवार (2 जून) दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस बीच आरोपी यश यादव ने NEET-UG परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें रखने की अनुमति मांगी. इसके लिए यश ने आवेदन किया है. यह परीक्षा 21 जून को होनी है. आरोपी यश यादव का कहना है कि उसे NEET-UG परीक्षा देना है और इसकी तैयारी के लिए उसे किताबों की जरूरत है. ऐसे में उसने कोर्ट में एक आवेदन देकर किताबें रखने की अनुमति मांगी है.

आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ी

आज आरोपी मंगिलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद इन्हें पेश किया गया था. कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ा दी है.

दो और आरोपी गिरफ्तार

NEET-UG पेपर लीक मामले में आए दिन नए-नए खुलासे हो रही है. महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में CBI इस मामले की जांच कर रही है. कुछ दिन पहले इस मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें लातूर का एक डॉक्टर भी शामिल था. CBI के अनुसार आरोपी डॉक्टर डॉ. शिरुरे ने 3 छात्रों को कैमिस्ट्री के पेपर दिलवाए थे. इनमें एक आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक का बेटा भी था. जांच में सामने आया कि पेपर आरोपी पी. वी. कुलकर्णी से हासिल किए गए थे. वहीं, दूसरा गिरफ्तार आरोपी तेजस हर्षदकुमार शाह था. तेजस पुणे के डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी (APMA) में फिजिक्स का फैकल्टी है. आरोप है कि उसने गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवालदार से NEET-UG 2026 के लीक फिजिक्स प्रश्न हासिल किए थे..

क्षणिक स्वार्थ से नागरिक बोध तक: एक आवश्यक वैचारिक बदलाव की आवश्यकता

मनुष्य को पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी माना जाता है। उसके पास सही और गलत, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय में अंतर करने की अद्भुत क्षमता है। हमारा अनुभव, शिक्षा, सामाजिक मूल्य और कानून इस विवेक को और निखारते हैं। इसके बावजूद, एक कड़वा और विचित्र सच यह है कि हममें से अधिकांश लोग अनेक गंभीर गलतियाँ जानबूझकर करते हैं। हम भली-भांति जानते हैं कि हमारा आचरण अनुचित है और इसके परिणाम आत्मघाती हो सकते हैं, फिर भी हम उन्हें बार-बार दोहराते हैं। आज के मशीनी और उपभोक्तावादी युग में यह केवल भारतीय समाज की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण वैश्विक मानव समाज की एक सहज प्रवृत्ति बन चुकी है। हाँ, भारत जैसे विशाल, घनी आबादी और सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश में यह समस्या अधिक मुखर और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।?उदाहरण के लिए, हम सब जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। तेज हॉर्न, अनियंत्रित डीजे और लाउडस्पीकर का शोर बच्चों, वृद्धों, रोगियों और बेजुबान जानवरों को असहनीय पीड़ा देता है, साथ ही विद्यार्थियों की एकाग्रता को भंग करता है। इसके बावजूद, विवाह, धार्मिक आयोजनों और राजनीतिक रैलियों में हम ध्वनि की गरिमा और कानूनी मर्यादा को ताक पर रख देते हैं।

» यही स्थिति पर्यावरण को लेकर भी है। सड़कों पर कूड़ा फेंकना, नदियों, तालाबों और पूजनीय जलाशयों में प्लास्टिक, रासायनिक अपशिष्ट और यहाँ तक कि पूजा-सामग्री बहा देना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। हम जानते हैं कि भूजल, कोयला और पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, फिर भी हम उनका बेरहमी से दोहन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) और जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोज महसूस करने के बाद भी 'विकास' के मुखौटे के पीछे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी है, और समाज में इसके प्रति कोई सामूहिक पश्चाताप नहीं दिखता।

» यातायात नियमों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। लाल बत्ती (रेड लाइट) पार करना, हेलमेट न लगाना, सीट बेल्ट से परहेज करना और 'रॉन्ग साइड' (गलत दिशा) में वाहन दौड़ाना, वाहन चलाते मोबाइल का उपयोग करना आदि को बहादुरी का प्रतीक मान लिया जाता है। प्रदूषण फैलाते वाहनों से पर्यावरण को बीमार करने में हमें कोई झिझक नहीं होती। त्रासदी यह है कि जब इन गलतियों के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो हम अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय तुरंत व्यवस्था, प्रशासन या सड़कों को दोष देकर पल्ला झाड़ लेते हैं।

» यही प्रवृत्ति हमारे सामाजिक और नैतिक जीवन में भी दिखती है। झूठ बोलना, अनुचित लाभ उठाना, भ्रष्टाचार, कर चोरी (टैक्स चोरी), सार्वजनिक विमर्श में अभद्र भाषा का प्रयोग और धोखाधड़ी जैसे कृत्य अब समाज में सामान्य माने जाने लगे हैं। सवाल यह उठता है कि जब हमारी चेतना यह मानती है कि यह सब गलत है, तो फिर हमारा व्यवहार इसके ठीक उलट क्यों होता है?

मनोविज्ञानी और समाजशास्त्री इसके पीछे चार मुख्य कारण मानते हैं:

पहला,?तात्कालिक लाभ की प्रवृत्ति मनुष्य का दिमाग दूरगामी नुकसान की तुलना में तत्काल मिलने वाले छोटे से लाभ को अधिक महत्व देता है। जैसे लाल बत्ती तोड़कर दो मिनट बचा लेने का 'तात्कालिक लाभ' उसे संभावित दुर्घटना के 'दूरगामी खतरे' से अधिक आकर्षक लगता है। पेड़ बेचकर तुरंत मिलने वाला पैसा, भविष्य के पर्यावरणीय संकट पर भारी पड़ जाता है।दूसरा,

सामूहिक अनुकरण। जब लोग देखते हैं कि समाज में बहुसंख्यक लोग नियमों को तोड़ रहे हैं और उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है, तो वे भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। धीरे-धीरे यह सामूहिक अनाचार सामाजिक स्वीकृति पा लेता है। जैसे कचरा फेंकने वाला हर व्यक्ति यही सोचता है कि 'जब पूरी सड़क ही गंदी है, तो मेरे एक रैपर फेंकने से क्या फर्क पड़ जाएगा? 'तीसरा,?दंड के भय का अभाव। जिन देशों में कानून का शासन कठोर और निष्पक्ष होता है, वहाँ नागरिक चाहकर भी नियम तोड़ने का साहस नहीं करते। इसके विपरीत, जहाँ लचर कानून व्यवस्था या 'प्रभाव' के दम पर बच निकलने का रास्ता खुला हो, वहाँ अपराधियों और नियम तोड़ने वालों का साहस बढ़ जाता है। चौथा,?नैतिक शिक्षा और नागरिक बोध की कमी। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल उपाधियाँ (डिग्रियां) बांटने और रोजगार सुरक्षित करने का माध्यम बनकर रह जाती है, तो चरित्र निर्माण का मुख्य उद्देश्य पीछे छूट जाता है। ऐसे में हम साक्षर और तकनीकी रूप से सक्षम लोग तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार 'नागरिक' गढ़ने में असफल हो जाते हैं।

भारतीय दर्शन में इस मानवीय भटकाव का उत्तर बहुत पहले दे दिया गया था। हमारे मनीषियों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार (षड्रिपु) को तमाम गलतियों का मूल कारण बताया है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि आत्म-नियंत्रण की कमी और अनियंत्रित स्वार्थ ही मनुष्य से गलत निर्णय करवाते हैं।

मेरा ऐसा मानना है कि ?इस जटिल समस्या का समाधान केवल कड़े कानून बनाने या नए जुर्माने तय करने से नहीं होगा। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।व्यक्तिगत आचरण में सुधार, व्यापक सामाजिक जागरूकता, प्राथमिक स्तर से ही मूल्यों पर आधारित शिक्षा और बिना किसी भेदभाव के त्वरित व प्रभावी दंड व्यवस्था।?जब तक हम यह आत्मसात नहीं करेंगे कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही समाज, पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है, तब तक कोई सकारात्मक बदलाव संभव नहीं है। वास्तव में, यक्ष प्रश्न यह नहीं है कि हम अनजाने में गलतियाँ क्यों करते हैं; प्रश्न तो यह है कि 'सही क्या है'—यह भली-भांति जानते हुए भी गलत करने का दुस्साहस हमारे भीतर कहाँ से आता है? जिस दिन हमारा आत्म-विवेक, हमारे क्षणिक स्वार्थ पर विजय प्राप्त कर लेगा, ठीक उसी दिन से एक स्वस्थ, समृद्ध और सभ्य समाज का पुनर्जन्म होगा।

प्रो.(डा.)मनमोहन प्रकाश

एनएचएम के संविदा कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की सुध लेने वाला कोई नहीं

संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, महामारी नियंत्रण और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को जमीन पर उतारने का जिम्मा इन्हीं संविदा कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के कंधों पर है। फिर भी, दशकों से ये वही लोग सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। वेतन में देरी, नियमितीकरण की मांग पर खामोशी, न्यूनतम सुविधाओं का अभाव और शोषण की संस्कृति - यह सब जारी है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मई 2026 में एनएचएम के हजारों संविदा कर्मचारियों ने दो-तीन महीने के लंबित मानदेय को लेकर 'नो पे नो वर्क' का प्रदर्शन किया। सोनभद्र, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई, पीलीभीत समेत कई जिलों में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया या धरना दिया। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है - बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, दवाइयाँ सब प्रभावित हो रहे हैं।

समस्या की गहराई

एनएचएम के तहत काम करने वाले कर्मचारी वर्षों से संविदा पर हैं। कई जगह 10-15 साल या उससे ज्यादा सेवा देने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारियों जितना वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल सुविधा या जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्य 'स्थायी काम को संविदा के नाम पर शोषण' नहीं कर सकता। 10 साल से ज्यादा सेवा देने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति अलग है। यहां अदालतें भी कई बार कह चुकी हैं कि संविदा कर्मचारियों को स्वतः नवीनीकरण का अधिकार नहीं है। परिणामस्वरूप, कर्मचारी अनिश्चितता के साए में काम करते हैं। महामारी के समय जब इन्हीं कर्मचारियों ने जान की बाजी लगाकर ड्यूटी की, तब भी बीमा और अतिरिक्त सुविधाएं देने में कोताही बरती गई।

मांगें जायज हैं

- समय पर वेतन भुगतान
- समान काम के लिए समान वेतन
- लंबे समय से सेवा देने वालों का नियमितीकरण
- सामाजिक सुरक्षा (बीमा, मातृत्व अवकाश, मेडिकल लीव) - वेतन विसंगतियों को दूर करना

ये मांगें नई नहीं हैं। 2021 में भी यूपी में बड़े प्रदर्शन हुए थे। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में भी इसी तरह की हड़तालें हो चुकी हैं।

सरकारी तर्क और हकीकत

सरकार का तर्क है कि एनएचएम केंद्र प्रायोजित योजना है, फंड की कमी रहती है। लेकिन सवाल यह है कि जब योजनाएं चलानी हैं तो कर्मचारियों को भूखा क्यों रखा जाता है? स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी देशव्यापी समस्या है, फिर भी संविदा प्रथा को खत्म करने की बजाय उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। यह न सिर्फ कर्मचारियों के साथ अन्याय है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कमजोरी भी है। अगर कर्मचारी अनिश्चितता में रहेंगे तो समर्पण और गुणवत्ता कैसे बनी रहेगी?

समाधान की दिशा

सरकार को एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। जिन कर्मचारियों ने 8-10 साल या उससे ज्यादा सेवा दी है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाया जाए। फंड रिलीज को समयबद्ध किया जाए ताकि वेतन में देरी न हो। एनएचएम के बिना ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था लकवाग्रस्त हो जाएगी। आशा वर्कर्स, एएनएम, डेटा ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर - सभी इस मिशन के अंग हैं। इनकी उपेक्षा करना राष्ट्र की उपेक्षा है। समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें।प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी 'अराजक' नहीं, बल्कि पीड़ित हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं - यह वाक्य दुखद है, लेकिन सच्चा है। अब इसे बदलने की जिम्मेदारी सत्ता के गलियारों में है। स्वास्थ्य मिशन तभी सफल

महंगाई की चक्की में पिसता वो अनाज, जिसकी रोटी सब खा रहे हैं

[खामोश राख बनती वो ईंट, जिस पर महल खड़े हो रहे हैं]

[मध्य वर्ग— जिसकी हथेली पर टिका है भारत, वही सबसे खाली क्यों है?]

भारत की आर्थिक कहानी में एक ऐसा पात्र है जो हर अध्याय में मौजूद रहता है, लेकिन जिसकी पीड़ा अक्सर फुटनोट बनकर रह जाती है। यह पात्र है—मध्य वर्ग। यह वही जीवन है जो हर सुबह उम्मीद जोड़ता है और हर रात हिसाब में उलझकर टूटता थोड़ा और है। विकास, कर और उपभोग की सबसे भारी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है, फिर भी सुविधाएँ इसके हिस्से में हमेशा कम पड़ जाती हैं। न यह इतना कमजोर है कि योजनाओं का पूरा लाभ ले सके, न इतना सक्षम कि महंगाई और करों का दबाव सहज झेल पाए—इसलिए यह लगातार सिकुड़ती आर्थिक खाई में फँसता जा रहा है। वर्ष 2026 में स्थिर आय, बढ़ती कीमतें और ईंधन का बोझ इसे और अधिक नीरव पीड़ा में धकेल रहे हैं।

अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाने वाला मध्य वर्ग आज उसी व्यवस्था के सबसे तीखे दबाव में है—विडंबना यह कि जिस मशीन को वह चलाता है, उसका सबसे भारी बोझ भी वही उठाता है। उपभोग, कर और नकदी प्रवाह की धुरी होने के बावजूद उसकी आय का अधिकांश हिस्सा रोज़मर्रा खर्चों में ही समाप्त हो जाता है; शहरों में किराया कमाई को निगलता है, ईएमआई आय को जकड़ती है, राशन और शिक्षा का बढ़ता खर्च लगातार दबाव बनाता है। कर राहतें महंगाई की रफ्तार के आगे कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे बचत घटती है और भविष्य और अधिक अनिश्चित होता जाता है।

कीमतों की चुपचाप उठती लहरें सबसे पहले मध्य वर्ग की जेब से टकराती हैं, क्योंकि उसके पास बचाव की गुंजाइश सबसे कम होती है। पेट्रोल-डीजल महँगा होता है तो असर सिर्फ गाड़ी तक नहीं रहता—परिवहन से लेकर रसोई, बाजार और हर जरूरी सेवा की कीमतें ऊपर चढ़ जाती हैं। सब्ज़ी, दूध, दाल और रोज़मर्रा का सामान लगातार बजट को अस्थिर करता रहता है, जबकि आय उसी रफ्तार से नहीं बढ़ती। चिकित्सा खर्च तेज़ी से बढ़ रहा है और शिक्षा की लागत भी हर साल नई ऊँचाई छू रही है। न मुफ्त इलाज का सहारा है, न पूरी तरह सस्ती शिक्षा का विकल्प—हर सेवा का पूरा मूल्य चुकाकर ही यह वर्ग अपनी जरूरतें पूरी करता है।

करों की अदृश्य परतें जब आम जीवन पर चढ़ती हैं, तो सबसे पहले मध्य वर्ग की सांसें भारी हो जाती हैं। आयकर का सबसे बड़ा हिस्सा देने के बावजूद यह वर्ग लाभों की कतार में अक्सर पीछे रह जाता है। एक ओर गरीब वर्ग को योजनाओं और सब्सिडी का सहारा मिलता है, दूसरी ओर संपन्न वर्ग कर-योजनाओं से राहत निकाल लेता है—पर इनके बीच खड़ा मध्य वर्ग न पर्याप्त सहायता पा पाता है, न कर बचाने की सुविधा। बिजली, पानी, किराया और हर उपभोग वस्तु पर सीधे-परोक्ष करों का दबाव उसकी जेब को लगातार हल्का करता रहता है। नतीजतन, आय बढ़ने के बावजूद उसकी वास्तविक खरीद क्षमता धीरे-धीरे घटती जाती है।

सपनों की बुनियाद माने जाने वाले आवास और शिक्षा आज मध्य वर्ग के लिए सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बन चुके हैं। महानगरों में किराया इतना बढ़ गया है कि आय का बड़ा हिस्सा सिर्फ छत बचाने में ही निकल जाता है, जबकि घर खरीदने का सपना लंबी ईएमआई और भारी ब्याज के बोझ में उलझकर रह जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी अब सस्ती नहीं रही—स्कूल फीस, परिवहन, कोचिंग और गतिविधियों के खर्च मिलकर परिवार के बजट को लगातार दबाते रहते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ते बीमा प्रीमियम और सीमित कवरेज हर अचानक बीमारी को आर्थिक अस्थिरता का कारण बना देते हैं, जिससे वर्षों की योजना पल भर में बिखर सकती है।

आर्थिक दबाव अब सिर्फ खातों की गणना नहीं रहा, यह जीवन की सोच और मनोस्थिति तक उतर आया है। बेहतर जीवन की चाह में लोग कर्ज और ईएमआई के ऐसे जाल में उलझते जा रहे हैं, जहाँ इच्छाएँ बार-बार टलती हैं और जरूरतें लगातार आगे खिसकती जाती हैं। भविष्य के लिए बचत और निवेश की योजनाएँ आज के खर्चों के सामने कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे सुरक्षा की भावना धीरे-धीरे धुंधली होती जाती है। युवा पीढ़ी इस असंतुलन को देखकर भरोसे की जगह उलझन महसूस कर रही है—शिक्षा, नौकरी और स्थिरता के पुराने भरोसे अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। यह स्थिति केवल आय-व्यय का अंतर नहीं, बल्कि उम्मीदों और हकीकत के बीच गहराती खामोश दूरी का संकेत है।

यह स्थिति केवल घरों की सीमाओं में कैद नहीं रहती, बल्कि पूरे देश की आर्थिक धड़कन को प्रभावित करती है। जैसे ही मध्य वर्ग की क्रय शक्ति घटती है, बाजार की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है, उपभोग कम होता है और विकास की गति पर सीधा असर दिखता है। इसलिए इसकी समस्याओं को व्यक्तिगत बोझ मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जरूरत है वास्तविक कर सुधार, महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण, स्वास्थ्य-शिक्षा में लक्षित राहत, ईंधन करों में संतुलन और किफायती आवास नीतियों की। अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इस वर्ग को स्थिरता नहीं मिली, तो विकास की पूरी संरचना धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती है।

राष्ट्र निर्माण की धुरी अब एक नए दृष्टिकोण की माँग कर रही है, जहाँ मध्य वर्ग को केवल करदाता नहीं बल्कि वास्तविक भागीदार माना जाए। वर्षों से यह वर्ग विकास की कीमत चुकाता आया है, लेकिन अब उसके धैर्य और क्षमता दोनों की सीमाएँ स्पष्ट होने लगी हैं। जो वर्ग अर्थव्यवस्था को गति देता है, वही यदि असुरक्षा, कर्ज और अनिश्चितता के दबाव में आ जाए, तो यह स्थिति पूरे देश के लिए चेतावनी बन जाती है। जैसे शरीर की ताकत रीढ़ पर टिकी होती है, वैसे ही किसी राष्ट्र की स्थिरता मध्य वर्ग पर निर्भर करती है—और यदि यही रीढ़ कमजोर पड़ जाए, तो विकास की चमक भी लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

पृथ्वी की पुकार

जब प्रथम मनुष्य ने
गुफा की दीवारों पर जीवन के चित्र उकेरे थे,
तब उसकी उँगलियों में विजय का नहीं, प्रकृति के प्रति विस्मय का रंग था।
जब वेदों के मंत्रों में नदियाँ माता कही गई,
जब अरण्यक वन की नीरवता में रचे गए,
जब पर्वतों को देव और वृक्षों को वंदनीय माना गया, तब सभ्यता ने सीखा था– धरती उत्तराधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है।
किन्तु इतिहास की राह में
एक दिन मनुष्य ने अपनी ही सीमा लाँघ दी। उसने नदियों को बाँधों में कैद कर लिया,
वनों को बाज़ारों की वस्तु बना दिया, और धुएँ की चादर से आकाश का नीला चेहरा ढँक दिया।
लोहे की भूख बढ़ती गई,
कंक्रीट के जंगल फैलते गए, और असली जंगल
मानचित्रों से मिटते गए।
गंगा ने अपने तटों पर कचरे का बोझ सहा,
हिमालय ने अपनी बर्फ़ीली चुप्पी में पिघलने का दर्द छिपाया,
समुद्रों ने प्लास्टिक के घाव सँजोए,
और ऋतुएँ अपने ही समय से भटक गई।
इतिहास साक्षी है–
जब-जब मनुष्य ने प्रकृति को लूटा है, प्रकृति ने प्रतिशोध नहीं, परिणाम दिया है।
सूखे पड़े, बाढ़ें आई,
तूफानों ने नगरों का अभिमान तोड़ा, और तपती धरती ने चेतावनी दी–'तुम्हारी प्रगति यदि मेरे अस्तित्व पर खड़ी है,
तो वह प्रगति नहीं, पराजय है।
'किन्तु इसी इतिहास में
अमर हैं वे हाथ भी
जिन्होंने वृक्षों को कटने से बचाने के लिए
अपने प्राणों का कवच बना लिया।
अमर हैं वे स्त्रियाँ
जिन्होंने तनों से लिपटकर कहा– 'पहले हमें काटो, फिर वन को। 'अमर हैं वे गाँव
जिन्होंने सूखी धरती पर
जल की हर बूँद को पूजा की तरह सँजोया।
और अमर हैं वे बच्चे
जो आज भी एक पौधा लगाते समय
भविष्य के लिए प्रार्थना बोते हैं।
इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की पुकार
केवल एक आयोजन नहीं,
एक ऐतिहासिक संकल्प है–
प्लास्टिक प्रदूषण का अंत।
क्योंकि यह केवल कचरा नहीं,
समय के माथे पर लगा वह कलंक है
जो नदियों की साँस रोक रहा है, समुद्रों की गहराई घायल कर रहा है,
और आने वाली पीढ़ियों का अधिकार छीन रहा है।
आओ, फिर उसी प्राचीन स्मृति में लौटें
जहाँ पृथ्वी माता थी, जल जीवन था, वन संस्कृति थे,
और मनुष्य संरक्षक था।
आओ, ऐसा इतिहास लिखें
जिसे पढ़कर आने वाली शताब्दियाँ कहें–
'जब पृथ्वी संकट में थी,
तब कुछ लोगों ने केवल भाषण नहीं दिए; उन्होंने वृक्ष लगाए,
नदियाँ बचाई, प्लास्टिक छोड़ा,
और अपने समय के विरुद्ध खड़े होकर
भविष्य के पक्ष में निर्णय लिया।
'तब धरती मुस्कराएगी, नदियाँ फिर गाएँगी, वन फिर श्वास लेंगे,
और मानव सभ्यता का सबसे सुंदर अध्याय
किसी युद्ध की विजय से नहीं,
प्रकृति के साथ पुनर्मिलन से लिखा जाएगा।
'इतिहास के सबसे महान विजेता वे नहीं होंगे
जिन्होंने धरती को जीता, बल्कि वे होंगे जिन्होंने धरती को बचाया।'

डॉ रामानुज पाठक

दैनिक राशिफल

मेष आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। **शुभ रंग:** लाल 7 **शुभ अंक:** 9

वृषभ रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। **शुभ रंग:** सफेद 7 **शुभ अंक:** 6

मिथुन आज व्यस्तता अधिक रहेगी। कार्यों में सफलता के लिए धैर्य बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। यात्रा के योग बन सकते हैं। **शुभ रंग:** हरा 7 **शुभ अंक:** 5

कर्क परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। **शुभ रंग:** चांदी 7 **शुभ अंक:** 2

सिंह नेतृत्व क्षमता का लाभ मिलेगा। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
शुभ रंग: सुनहरा 7 शुभ अंक: 1

कन्या आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। व्यापार में नई योजनाएं लाभदायक रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। **शुभ रंग:** हरा 7 **शुभ अंक:** 7

तुला भाग्य का साथ मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक मामलों में संतुलित व्यवहार रखें। निवेश के लिए दिन अच्छा है।
शुभ रंग: गुलाबी 7 **शुभ अंक:** 6

वृश्चिक कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग: मैरून 7 **शुभ अंक:** 8

धनु धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। करियर में प्रगति के संकेत हैं। यात्रा से लाभ मिल सकता है।
शुभ रंग: पीला 7 **शुभ अंक:** 3

मकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। **शुभ रंग:** नीला 7 **शुभ अंक:** 4

कुंभ साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ के नए स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। **शुभ रंग:** आसमानी 7 **शुभ अंक:** 11

मीन नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।
शुभ रंग: पीला 7 **शुभ अंक:** 7

भारत नेपाल सीमा विवाद के ऐतिहासिक और राजनीतिक आयाम

भारत और नेपाल के मध्य सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं जो विश्व पटल पर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 1751 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा है। दोनों राष्ट्रों के नागरिक बिना किसी विशेष अनुमति पत्र के एक दूसरे के देश में अबाध रूप से आ जा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ जैसे पवित्र स्थल दोनों देशों की आस्था को एक समान सूत्र में बांधते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच अत्यंत प्रगाढ़ पारिवारिक और सामाजिक संबंध हैं। आर्थिक रूप से भी नेपाल अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मुख्य रूप से भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर करता है। भारत नेपाल को पेट्रोलियम, खाद्यान्न, दवाइयाँ और बिजली जैसी आवश्यक वस्तुएँ निरंतर प्रदान करता है। वर्ष 1950 की शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के संबंधों की आधारशिला है। इस संधि ने नेपाल के नागरिकों को भारत में रोजगार और निवास करने के वे सभी अधिकार दिए हैं जो किसी भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। भारतीय सेना में गोरखा सैनिक इसका एक गौरवशाली प्रमाण हैं जो दशकों से भारत की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान देते आए हैं। इतनी गहरी मित्रता और निर्भरता के बावजूद दोनों देशों के बीच सीमा से जुड़े कुछ संवेदनशील विषय समय समय पर कूटनीतिक तनाव का कारण बनते रहे हैं।

हाल ही में काठमांडू के महापौर बालेन्द्र शाह के एक वक्तव्य ने इस पुराने सीमा विवाद को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। नेपाल की संसद और सार्वजनिक मंचों पर इस विषय ने एक नई बहस को जन्म दिया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि नेपाल के लोगों ने भी कुछ स्थानों पर भारतीय भूमि का उपयोग किया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दोनों देशों को कूटनीतिक वार्ताओं, इतिहासकारों और सर्वेक्षण विशेषज्ञों की सहायता से इस विवाद का स्थायी समाधान खोजना चाहिए। नेपाल की राजनीति में जहाँ अक्सर राजनीतिक लाभ लेने के लिए भड़काऊ भावनाएं फैलाई जाती हैं, वहाँ एक लोकप्रिय युवा नेता द्वारा इस प्रकार का संतुलित और दोनों पक्षों की कमियों को स्वीकार करने वाला वक्तव्य आना एक अप्रत्याशित घटना थी। उनके इस बयान का नेपाल के भीतर कड़ा विरोध भी हुआ जिसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि महापौर का आशय सीमा पार खेती और स्थानीय निवासियों द्वारा भूमि के उपयोग से था न कि किसी राजनीतिक कब्जे से।

भारत और नेपाल के बीच मुख्य सीमा विवाद कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और सुस्ता क्षेत्रों को लेकर है। कालापानी क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के पास स्थित है और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भारत, नेपाल और तिब्बत के त्रिकोणीय भूभाग के पास स्थित है। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद से भारत ने यहाँ अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के मुख्य मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। इस विवाद की ऐतिहासिक जड़ें वर्ष 1816 की सुगौली संधि में निहित हैं जो ब्रिटिश शासकों और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार महाकाली नदी को दोनों देशों के बीच की पश्चिमी सीमा माना गया था। सारा विवाद इस बात पर केंद्रित है कि महाकाली नदी का वास्तविक उद्गम स्थल कौन सा है। नेपाल का दावा है कि नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है जिसके आधार पर कालापानी और लिपुलेख उसके भूभाग का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी ओर भारत का स्पष्ट मानना है कि नदी का उद्गम कालापानी के पास से होता है और इसलिए यह पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है।

वर्ष 2020 में यह कूटनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुँच गया था जब भारत ने धारचूला से लिपुलेख तक एक नई सड़क का निर्माण किया ताकि तीर्थयात्रियों को सुविधा हो सके। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल सरकार ने अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी कर दिया जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया। इस कदम ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद को लगभग रोक दिया था। नेपाल के कुछ नेताओं ने इस विवाद में ब्रिटेन और चीन के साथ संवाद करने की बात भी कही थी। भारत हमेशा से यह दृढ़तापूर्वक मानता रहा है कि भारत और नेपाल के बीच का सीमा विवाद पूरी तरह से एक द्विपक्षीय विषय है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।

नेपाल के पूर्व कूटनीतिज्ञों और सीमा विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि भारत और नेपाल के बीच लगभग 97 प्रतिशत सीमा का निर्धारण सफलतापूर्वक हो चुका है और केवल कुछ ही स्थानों पर सीमा स्तंभों की स्थिति को लेकर भ्रम है। सुस्ता क्षेत्र का विवाद गंडक नदी के मार्ग बदलने के कारण उत्पन्न हुआ है। नदियों के प्राकृतिक बहाव में परिवर्तन अक्सर सीमावर्ती क्षेत्रों में नई चुनौतियाँ पैदा करता है जिनका समाधान तकनीकी और सर्वेक्षण समितियों द्वारा किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच संयुक्त सीमा कार्यसमूह पहले से ही इन विषयों पर कार्य कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो शेष 3 प्रतिशत विवादित सीमा का समाधान भी शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है।

वर्तमान भूराजनीतिक परिदृश्य में चीन का बढ़ता प्रभाव भी इस विवाद को जटिल बनाता है। चीन नेपाल में भारी मात्रा में आर्थिक निवेश कर रहा है और सड़क, रेल तथा अन्य आधारभूत ढांचों का निर्माण कर रहा है। भारत की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि नेपाल के साथ उसके संबंध मधुर बने रहें ताकि कोई अन्य देश इस कूटनीतिक दूरी का लाभ न उठा सके। नेपाल भी एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत और नेपाल के संबंध केवल नक्शों और सीमा रेखाओं के मोहताज नहीं हैं। दोनों देशों के नागरिकों के बीच जो गहरा विश्वास और आत्मीयता है वह किसी भी कूटनीतिक विवाद से कहीं अधिक शक्तिशाली है। भड़काऊ बयानों के स्थान पर ऐतिहासिक दस्तावेजों, तथ्यों और व्यावहारिक कूटनीति के आधार पर समाधान खोजना ही एकमात्र विकल्प है। यदि दोनों देश परस्पर सम्मान और संवाद की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखते हैं तो सीमा विवाद को सुलझाना कोई असंभव कार्य नहीं है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध दक्षिण एशिया के निर्माण हेतु भारत और नेपाल की अटूट मित्रता अत्यंत आवश्यक है।

महेन्द्र तिवारी

स्वामी– स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

रामपुर सनेता गांव में रास्ते पर अवैध कब्जा करने का लगाया आरोप

कोंच(जालौन)- विकास खंड कोंच क्षेत्र के ग्राम रामपुर सनेता निवासी ग्रामीण ने सोमवार को एसडीएम हेमंत पटेल को शिकायती पत्र देकर गांव के एक व्यक्ति पर आम रास्ते में अतिक्रमण कर लेने और विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ग्रामीण राजेन्द्र सिंह पटेल ने एसडीएम को दिए शिकायती पत्र में बताया कि गांव में इन दिनों शनिदेव मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक सार्वजनिक मार्ग है जिसका उपयोग श्रद्धालुगण आवागमन में करते हैं। गांव के ही एक व्यक्ति ने इसी रास्ते में अपने मकान के सामने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली रखता है साथ ही पशुओं को बांधता है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जब गांव के लोग विरोध करते हैं तो वह गाली-गलौज कर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है। इतना ही नहीं, मामले की अधिकारियों से शिकायत करने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने लगता है जिससे ग्रामीण उक्त व्यक्ति के भय और दबाव में रहने पर मजबूर हैं। शिकायतकर्ता ने एसडीएम से मांग की है कि मामले का संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक मार्ग से अवैध रूप से खड़े किए गए वाहन और पशु तत्काल हटवाये जाएं और उक्त व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

गूल और नरियों को पूर कर की जा रही प्लाटिंग

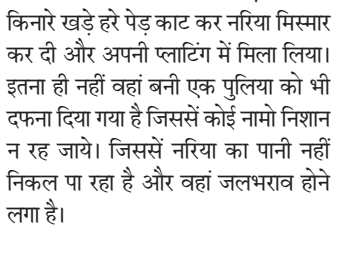

कोंच(जालौन)- कोंच में सरकारी गूल और नरियों को पूर कर दबंगई के बल पर भूमाफियां प्लाटिंग का व्यापार कर रहे है। जिससे बारिश के मौसम में पूरे नगर को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है और किसानों को सिलाई के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। यह काम चोरी छिपे नहीं हो रहा है भूमाफियां खुलेआम गूलें और नरियों को पूरने का काम कर रहे है। यह काम कस्बे के चारों तरफ हो रहा है फिर भी प्रशासन मौन बैठा हुआ है। कोंच के चारों तरफ बड़े पैमाने पर प्लाटिंग का व्यापार हो रहा है जिसके सरकारी गूल और नरियों को भी बिस्मार कर मिलाया जा रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है। कोंच-कैलिया मार्ग पर ताज गार्डन के ठीक सामने समीर व रसीद के खेत थे उसके आगे सड़क किनारे नरिया निकली है। जिसके पानी से आस पास के किसान सिंचाई करते है और बारिश का पानी भी निकलता रहता है। नरिया के कुछ दिनों पहले भूमाफियों ने खेत खरीद कर प्लाटिंग का व्यापार करने के लिए नरिया के किनारे खड़े हरे पेड़ काट कर नरिया मिस्मार कर दी और अपनी प्लाटिंग में मिला लिया। इतना ही नहीं वहां बनी एक पुलिया को भी दफना दिया गया है जिससें कोई नामो निशान न रह जाये। जिससें नरिया का पानी नहीं निकल पा रहा है और वहां जलभराव होने लगा है।

यूपी के कृषि विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मेनका बनीं लखनऊ की जिला कृषि अधिकारी

लखनऊ। कृषि विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने 27 जिला स्तरीय अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इनमें कुशीनगर की जिला कृषि अधिकारी मेनका को जिला कृषि अधिकारी लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही 18 उपनिदेशक के स्थानांतरण के साथ नवप्रोन्नत संयुक्त निदेशक और उप निदेशकों को भी तैनाती दी गई है। विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार जिला कृषि अधिकारी गगन दीप सिंह को आजमगढ़ से जालौन, राजीव कुमार भारती को ललितपुर से सहारनपुर, देवेंद्र प्रताप सिंह को गोरखपुर से बलिया, राजपति शुक्ल को चित्रकूट से सुलतानपुर, सदानंद चौधरी को सुल्तानपुर से आजमगढ़, उमेश कुमार गुप्ता को कानपुर देहात से श्रावस्ती और दुर्गेश कुमार सिंह को महोबा से औरैया भेजा गया है। पांच उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारियों और तीन भूमि संरक्षण अधिकारियों को जिला कृषि अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें शिव शंकर चौधरी को कौशांबी, सतीश कुमार को कासगंज, विनीत कुमार को पीलीभीत, रंजीत कुमार चौरसिया को ललितपुर, अमित कुमार को चित्रकूट, देवेंद्र सिंह निरंजन को अमेठी, राजमंगल चौधरी को गोरखपुर और सौरभ वर्मा को अयोध्या का जिला कृषि अधिकारी बनाया गया है। खीरी के प्रक्षेत्र प्रबंधक संजीव कुमार सिंह को कुशीनगर और लखनऊ की आलमबाद प्रयोगशाला में तैनात उर्वरक विश्लेषक अरुणेश प्रताप सिंह को कानपुर नगर में जिला कृषि अधिकारी के पद पर भेजा गया है।

मलिहाबाद के घुसौली गांव में नालियों का पानी सड़क पर, डेढ़ साल से ग्रामीण परेशान, प्रदर्शन की चेतावनी

● .....3 किमी दूर ब्लॉक, फिर भी बदतर हाल! घुसौली में गंदे पानी से जूझ रहे ग्रामीण।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद, लखनऊ। मलिहाबाद ब्लॉक से महज लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत घुसौली में बदहाल व्यवस्था ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। गांव में नालियों के पानी का उचित निकास न होने के कारण गंदा पानी महीनों से सड़क पर बह रहा है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पूरे रास्ते पर जलभराव बना हुआ है और लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं बल्कि करीब पिछले डेढ़ साल से लगातार बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और ग्राम पंचायत की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें रोजाना इसी गंदे और बदबूदार पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार बरसात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

गांव वालों का कहना है कि मलिहाबाद ब्लॉक इतनी कम दूरी पर होने के बावजूद यदि ग्राम पंचायत की यह हालत है तो दूरदराज की पंचायतों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर कई बार ग्राम प्रधान अयोध्या प्रसाद से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई और समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सचिव केवल ब्लॉक में बैठकर काम करता है और गांव की समस्याओं को देखने या सुनने के लिए कभी गांव नहीं आता। इसी कारण गांव की मूलभूत समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।

सड़क पर भरे गंदे पानी के कारण गांव में बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव और गंदगी के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों का डर बना हुआ है। ग्रामवासियों ने प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नालियों की सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं कराई गई, तो वे मलिहाबाद तहसील और ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

माध्यमिक विद्यालय द्वारा हाई स्कूल इंटर के छात्र-छात्राओं को सर्वाधिक अंक आने पर सम्मानित किया गया

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के कैंट तोप खाना माध्यमिक विद्यालय छावनी परिषद के प्रेक्षा ग्रह में आज समर कैंप का समापन आयोजित किया गया, इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, खचाखच दर्शकों से भरे इस प्रेक्षा ग्रह में तालियों की गूंज से नन्हे बच्चों की कला को सराहा गया। खास बात ये थी कि इंटर हाइ स्कूल की बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित कर उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को नामित सदस्य छावनी परिषद रक्षा मंत्रालय भारत सरकार प्रमोद शर्मा द्वारा साइकिलें भेंट कर उनका उत्साह वर्धन किया गया और उनके साथ पधारे उनके माता पिता को भी पुष्प गुच्छ दे कर सम्मानित किया गया,इस आयोजन के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कैंट सुरेश तिवारी अधिशासी अधिकारी, अभिषेक ठाकुर, नामित सदस्य छावनी परिषद, प्रमोद शर्मा व उनकी धर्म पत्नी, डॉ0 रंजीता शर्मा, फिल्म निर्देशक योगेश त्रिपाठी, एल0बी0 एस स्कूल के उपप्रबंधक मो0 जावेद सभी ब्रांच की प्रधानाचार्य पूर्व सदस्य छावनी परिषद अंजुम आरा, अशफाक कुरैशी सहित कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामई उपस्थिति रही, आपको बता दे इस स्कूल ने मुमताज जैसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी देश को दी है जो आज पचास से अधिक देशों में भारतीय हॉकी खेल कर भारत का परचम लहरा चुकी हैं।

ओपन जिम की बदहाली से लोगों में नाराजगी, लाखों की लागत से बनी सुविधा बेकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। नगर के आलमपुर रोड स्थित बैसवारा इंटर कॉलेज के खेल मैदान के पास नगर पंचायत द्वारा स्थापित ओपन जिम रखरखाव के अभाव में बदहाली का शिकार हो गया है। करीब दो वर्ष पहले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाए गए इस जिम में शुरुआती दिनों में युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों की अच्छी-खासी भीड़ रहती थी, लेकिन अब अधिकांश उपकरण खराब हो चुके हैं।

जिम में लगी कई मशीनें अपनी जगह से उखड़ गई हैं, जबकि कुछ उपकरण टूटकर जमीन पर पड़े हुए हैं। कई मशीनें पूरी तरह अनुपयोगी हो चुकी हैं, जिससे यहां आने वाले लोगों को व्यायाम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब उपकरण किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।

नगर पंचायत ने इस ओपन जिम की स्थापना पर लाखों रुपये खर्च किए थे, लेकिन नियमित रखरखाव न होने के कारण इसकी हालत लगातार खराब होती चली गई। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से मरम्मत की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ओपन जिम की बदहाल स्थिति को लेकर बच्चों, युवाओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों में नाराजगी है। स्थानीय नागरिकों ने नगर पंचायत से जल्द से जल्द उपकरणों की मरम्मत कर जिम को पुनः संचालित कराने की मांग की है, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।

गांवों में लगेगी अदालत, 1200 लंबित मुकदमों के निस्तारण की तैयारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। तहसील क्षेत्र में लंबित राजस्व मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत चयनित गांवों में ही अदालत लगाकर शिकायतों और लंबित वादों की सुनवाई की जाएगी। इस अभियान को 'आपका गांव, आपकी अदालत' नाम दिया गया है। तहसीलदार शिवम राठौर ने बताया कि जल्द ही गांवों में अदालतों का आयोजन शुरू किया जाएगा। जिस गांव में अदालत लगेगी, वहां से संबंधित सभी लंबित मामलों की मौके पर सुनवाई होगी। वादकारियों को पूर्व सूचना देकर निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहने को कहा जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बात सुनने के साथ ही गांव के बुजुर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और सम्मानित लोगों का सहयोग भी लिया जाएगा। उनकी मौजूदगी में आपसी विवादों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उच्च न्यायालय के निर्देशों से संबंधित पत्रावलियों और तीन से पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। तहसील क्षेत्र के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार खीरों और नायब तहसीलदार सरेनी न्यायालयों में करीब 800 मामले विचाराधीन हैं, जबकि उपजिलाधिकारी न्यायालय में लगभग 400 मुकदमे लंबित हैं। अधिवक्ताओं की हड़ताल और अन्य कारणों से कई मामलों की नियमित सुनवाई नहीं हो पाने के कारण लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उपजिलाधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि गांववार लंबित वादों का विवरण तैयार किया जा रहा है। प्रक्रिया पूरी होते ही गांवों में अदालत लगाकर मामलों के त्वरित निस्तारण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

बिजली और नहरों में पानी की मांग को लेकर किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन

लालगंज (रायबरेली)। बिजली आपूर्ति और नहरों में पानी की समस्या को लेकर सोमवार को जय किसान जन कल्याण सेवा समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में पदाधिकारी ने बिजली व्यवस्था बहाल करने और नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग की। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने एसडीएम राजेश श्रीवास्तव को ज्ञापन देते हुए कहा कि क्षेत्र की नहरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। इससे किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है। वहीं कई गांवों में नलकूप और हैंडपंप भी पानी नहीं दे रहे हैं। तालाब सूख चुके हैं, जिससे ग्रामीणों के सामने पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश सरकार की ओर से बिजली आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन स्थानीय स्तर पर उनका प्रभाव नहीं दिख रहा है। इसका खामियाजा किसानों और ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। समिति ने क्षेत्र में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने और नहरों में शीघ्र पानी छोड़े जाने की मांग की है।

सड़क पर बह रहा ओवरफ्लो सीवर चैंबर का दूषित पानी, आमजन परेशान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोंच(जालौन)- नगर पालिका प्रशासन की लचर और लापरवाही भरी कार्यप्रणाली आमजन को रुला रही है। नगर की सबसे विकराल समस्या में शुमार सीवर अव्यवस्था है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है जिससे आमजन में गुस्सा नजर आ रहा है। नगर में स्टेट बैंक के रास्ते बाजार जाने वाले मार्ग पर जेडीसी बैंक के समीप सड़क पर सीवर उफनने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क मार्ग पर दिन भर बड़ी संख्या में पैदल और वाहन सवार लोगों का आवागमन बना रहता है। ओवरफ्लो सीवर चैंबर से ऊपर बहता दूषित पानी से आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सीवर चैंबर ओवरफ्लो हो रहा है लेकिन समस्या के समाधान के लिए अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। सड़क पर बहते दूषित पानी के कारण आसपास दुर्गंध फैल रही है जिससे आसपास रहने वाले लोगों और दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। आसपास के लोगों का आरोप है कि नगरपालिका कार्यालय में कई बार इस समस्या की जानकारी दी जा चुकी है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही सीवर की सफाई और मरम्मत नहीं कराई गई तो बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। आसपास के लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि समस्या का शीघ्र ही समाधान कराया जाए।

किसानों की समस्याओं पर भाकियू ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोंच(जालौन)- कोंच विकास खंड कार्यालय में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक अशोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें किसानों से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर उनके शीघ्र समाधान की मांग की गई।

बैठक में किसानों ने ब्लॉक क्षेत्र के कई गांवों में तालाबों के जीर्णोद्धार और भराव कार्य के अधूरे रहने का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि अधूरे कार्यों को जल्द पूरा किया जाए और अवैध कब्जों को हटाया जाए। किसानों ने विशेष रूप से चमारी और बसोब गांवों के तालाबों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। ग्राम पड़री में तालाबों, नालों और जल निकासी व्यवस्था की सफाई पर भी जोर दिया गया। किसानों ने बताया कि कई पात्र गरीब परिवारों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने ऐसे परिवारों का सर्वे कराकर आवास उपलब्ध कराने की मांग की।

इसके साथ ही वृद्धावस्था, विधवा और अन्य सामाजिक पेंशन योजनाओं से वंचित लोगों को पेंशन दिलाने की मांग भी उठाई। बैठक में टूटे विद्युत पोल बदलने, आवारा पशुओं को गोशालाओं में भेजने, नमामि गंगे योजना के अधूरे कार्य पूरे कराने, गांवों में चकरोड व नालियों का निर्माण तथा खराब हैंडपंपों की मरम्मत कराने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। किसानों ने बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि और आंधी से गेहूं की फसल को हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन और धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। बैठक में भाकियू तहसील अध्यक्ष चतुर सिंह पटेल, डॉ. पीडी निरंजन, सुभाष चंद्र पटेल, अनुरुद्ध पटेल, सौरभ पटेल, अशोक कुमार, सुनील कुमार, भवानीशंकर, विक्रम, महेंद्र कुशवाहा, वीरेंद्र, राजेश पटेल, कौशल पटेल, चित्तर सिंह, राजेश पटेल अटा, राजकुमार पटेल, रामशरण, कौशल कुशवाहा, प्रमोद कुमार आदि मौजूद रहे।

'चुनाव खर्च की व्यवस्था को 'इलेक्शन सरचार्ज' लगा रही भाजपा', अखिलेश ने बिजली सरचार्ज को लेकर साधा निशाना

● सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बिजली बिलों के माध्यम से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 'इलेक्शन सरचार्ज' लगाने का आरोप लगाया है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बिजली के बिल के नाम पर भाजपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के तिकड़मी खर्चों की व्यवस्था के लिए 'इलेक्शन सरचार्ज' लगा रही है। जून से बिजली का बिल देखकर लोगों के आंखों के आगे अंधेरा छाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली के बिल में भाजपा का कमीशन बढ़ा है।

सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा की कथनी-करनी में बहुत अंतर है। उसने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन जबसे सरकार आई है, रोज मंहगाई बढ़ाती जा रही है।

कभी डीजल, पेट्रोल, कभी बिजली और कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दे रही है। भाजपा, पूंजीपतियों के लिए नीतियां बनाती है। गरीबों की जेब से पैसा निकाल कर पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ाती है, फिर उनसे कमीशन और चंदे लेती है। प्रदेश की जनता भाजपा को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी तभी महंगाई से निजात मिलेगी।

जल्द जारी होगा पीडीए आडिट का दूसरा भाग

विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पीडीए की रणनीति को विस्तार देने में जुटी समाजवादी पार्टी अपने पीडीए आडिट का दूसरा भाग जारी करने की तैयारी में जुटी है। सोमवार को सपा प्रमुख ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। वीडियो में पेपर लीक को लेकर भाजपा को घेरा गया है। सूत्रों के मुताबिक पीडीए आडिट का दूसरा भाग विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक सबंधी आंकड़ों पर आधारित होगा।

टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी, तकनीकी खामी बता बोली खारिज करना उचित नहीं: हाई कोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए उत्तर पूर्व रेलवे (एनईआर) द्वारा उसकी तकनीकी बोली खारिज किए जाने की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि केवल स्टांप ड्यूटी की कमी जैसी सुधार योग्य तकनीकी खामी के आधार पर किसी बोलीदाता को टेंडर प्रक्रिया से बाहर करना उचित नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया कि सरकारी संस्थाएं टेंडर प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं तथा उनके निर्णय मनमाने नहीं होने चाहिए।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अभधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने एनईआर द्वारा तैयार की गई वित्तीय बोलियों की टेबुलेशन को निरस्त कर दिया। अदालत ने सभी पात्र निविदाकारों की वित्तीय बोलियों पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया है। साथ ही कोंकण रेलवे को तीन जून तक स्टांप ड्यूटी की कमी पूरी करने का निर्देश भी दिया गया है। मामला उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा जारी एक रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के टेंडर से जुड़ा है। कोंकण रेलवे का आरोप था कि उसकी तकनीकी बोली 19 मई 2026 को यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि वह पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करती, जबकि इसके लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। इसके बाद कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के निर्देश पर जब कंपनी ने टेंडर खारिज किए जाने का कारण पूछा, तब रेलवे प्रशासन ने बताया कि बैंक गारंटी के साथ प्रस्तुत स्टांप पेपर उत्तर प्रदेश स्टांप अधिनियम के अनुरूप नहीं था और उस पर देय स्टांप शुल्क कम जमा किया गया था। याची की ओर से दलील दी गई कि स्टांप ड्यूटी की कमी कोई गंभीर कानूनी बाधा नहीं बल्कि सुधार योग्य त्रुटि है। केवल इसी आधार पर बोली को खारिज करना न्यायसंगत नहीं है। यह भी कहा गया कि पूर्व में रेलवे प्रशासन इसी प्रकार की बैंक गारंटी स्वीकार कर चुका है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक अस्वीकृति पत्र में कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद नए कारण जोड़ने का प्रयास किया गया, जो कानून की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।

पीठ ने यह भी माना कि उपलब्ध तथ्यों से प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे कम वित्तीय बोली (एल-1) देने वाले याची को प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास किया गया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल एल-1 बोलीदाता होने से किसी कंपनी को ठेका मिलने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। अंततः कोर्ट ने वित्तीय बोलियों पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

मोहम्मद गुलाब के ईद मिलन कार्यक्रम में पहुंचे राजा वड़िंग, बोले- ईद-उल-अजहा प्रेम, भाईचारे और कुर्बानी का संदेश देती है

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लुधियाना। ईद-उल-अजहा (बकरीद) के पावन अवसर पर कांग्रेस नेता मोहम्मद गुलाब की ओर से एक ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष एवं लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय तलवाड़, पूर्व विधायक सरदार सिमरजीत सिंह बैंस, पार्षद गुरमीत सिंह मुंडियां, पार्षद हरविंदर सिंह कलेर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद लुधियाना के सदर कारी गयूर अहमद सहित शहर की कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुईं और मोहम्मद गुलाब को ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर मोहम्मद गुलाब और उनके साथियों ने सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा ईद की खुशियां एक-दूसरे के साथ साझा कीं। इस मौके पर अपने संबोधन में राजा वड़िंग ने कहा कि ईद-उल-अजहा कुर्बानी, त्याग, प्रेम और मानवता की सेवा का संदेश देती है। पंजाब की धरती हमेशा से भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक रही है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर प्रेम और एकता का संदेश देते हैं।

उत्तर प्रदेश में रोजगार क्रांतिः योगी सरकार की नीतियों से युवाओं को मिला सम्मान और सुरक्षा

रोजगार सिर्फ आय का साधन भर नहीं है, यह सामाजिक प्रतिष्ठा का, पारिवारिक सुरक्षा का, और मानवीय गरिमा का प्रश्न भी है। जब कोई सरकार इस यथार्थ को समझकर अपनी नीतियां बनाती है, तो उसके परिणाम केवल सांख्यिकीय नहीं होते, वे सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। किसी परिवार में जब पहली बार कोई सदस्य सरकारी सेवा में जाता है, तो वह केवल एक नौकरी नहीं पाता, वह उस परिवार में पीढ़ियों के संचित अभाव और प्रतीक्षा पर विराम लगाता है। वह एक ऐसा क्षण होता है जो पिछली पीढ़ी की दमित आकांक्षाओं को उड़ान देते हुए नई संभावना का द्वार खोलता है। ऐसे घरों में जब एक नियुक्ति पत्र आता है, तो वह केवल कागज नहीं होता, वह समूचे परिवार के त्याग व संघर्ष की सामूहिक जीत होती है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के सुखद भविष्य का यह अध्याय अनवरत लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 21 विभिन्न विभागों की विविध सेवाओं के लिए चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, किंतु यह संख्या अपने आप में पूरी कहानी नहीं कहती। मई माह का समग्र चित्र और भी व्यापक है। हालिया नियुक्तियों को मिलाकर केवल इसी माह में 2000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं।

कार्यालय खंड विकास अधिकारी हलिया मीरजापुर

पत्रांक / लेखाकार/ विधायक/ ई -निविदा 2025-26 दिनांक मार्च 2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विकासखंड हलिया जनपद मिर्जापुर के माध्यम से विधायक निधि के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से वित्तीय वर्ष 2025- 26 मे कराए जाने वाले कार्यों का विवरण जो वेबसाइट 222.etender.up.nic.in पर अपलोड है पर सामग्री आपूर्ति हेतु वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0 में पंजीकृत फर्मों से ही निविदा दिनांक 05-06-2026 से दिनांक 14-06-2026 तक ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधित समस्त जानकारी विवरण नियम और शर्तें वेबसाइट 222.etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगा।

सुनील कुमार खरवार
अवर अभियंता ग्रा0अ0वि0
हलिया, मीरजापुर।

विजय शंकर त्रिपाठी
खण्ड विकास अधिकारी
हलिया मीरजापुर।

संक्षिप्त खबरें

युवक को कपड़े से बांधकर जमीन पर लिटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

प्रेम प्रसंग का मामला, किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

सिद्धार्थनगर। जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सूर्यकुड़िया के टोला हथियागढ़ में एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर देकर लगाया। जिसपर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़कर कार्यवाही करते हुये जेल भेज दिया। चिल्हिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सूर्यकुड़ियां के टोला हथियागढ़ निवासी चंद्रावती पत्नी विजय कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि थाना क्षेत्र शोहरतगढ़ के गांधीनगर मोहल्ला निवासी चंद उर्फ जमाल खान (22) पुत्र मोहम्मद अली मेरी लड़की को 28 मई के दिन मेरी लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगाकर ले जा रहा था कि स्वजनों ने पीछा किया और वह लड़की को छोड़कर भाग गया।लड़की को घर वापस ले आए। पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पीड़िता ने की। पुलिस ने धारा 137 (2) व 87 के तहत केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब दो दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को ग्रामीण हाथ पैर कपड़े से बांधकर जमीन पर लिटाये हुए हैं। चर्चा है कि यह वीडियो उसी कथित आरोपी युवक का है। लेकिन वीडियो के सत्यता की पुष्टि स्वतंत्र प्रभात अखबार नहीं करता है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि पीड़िता की तहरीर पर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने किया ग्रामीणों संग भोज, शाहजहांपुर में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं

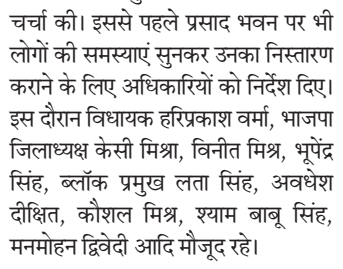

शाहजहांपुर। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स राज्यमंत्री जितिन प्रसाद रविवार को जलालाबाद के ककराहा गांव पहुंचे, यहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का प्रसारण सुना। इसके बाद वहीं पर टिफिन बैठक करके लोगों के साथ सहभोज भी किया।

ककराहा गांव में सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात

जितिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक को दिलाना उनकी प्रतिबद्धता है। इसके लिए हर जगह प्रशासन भी पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है यदि फिर भी जनमानस की किसी समस्या का समाधान में कोई कठिनाई आ रही हो तो वह जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी के नेताओं को अवगत कराएं ताकि उनकी समस्याओं का शीर्ष प्राथमिकता पर निदान कराया जा सके। मंत्री ने स्थानीय मुद्दों, समस्याओं को सुनकर उसके समाधानों पर चर्चा की। इससे पहले प्रसाद भवन पर भी लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान विधायक हरिप्रकाश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा, विनीत मिश्र, भूपेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख लता सिंह, अवधेश दीक्षित, कौशल मिश्र, श्याम बाबू सिंह, मनमोहन द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

50 लाख का बीमा और बहन का कत्ल... 9 साल से राजमिस्त्री बनकर छिपा था कातिल, ऐसे हुआ पर्दाफाश

नई दिल्ली। उत्तरी जिला के बुराड़ी थाना अंतर्गत अजीत विहार में 50 लाख के बीमे और लाखों की प्रापर्टी के लिए एक महिला की गला रेतकर हत्या करने में शामिल चंदन कुमार नाम के शख्स को क्राइम ब्रांच ने बिहार के लखीसराय से गिरफ्तार कर लिया है। वह वारदात के बाद पिछले नौ साल से फरार चल रहा था। बीमे की रकम और प्रापर्टी हड़पने के लिए कमल कुमार नाम के शख्स ने अपनी सगी बहन की अपने दो सगे साले चंदन कुमार व कुंदन कुमार के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। कमल कुमार को बुराड़ी थाना पुलिस ने अगस्त 2017 में घटना के कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके दोनों साले फरार थे, जिन्हें कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। उनमें चंदन को अब जाकर गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि कुंदन कुमार की 2018 में ही ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी है। डीसीपी, क्राइम ब्रांच, संजीव कुमार यादव के मुताबिक एसीपी संजय कुमार नागपाल और इंस्पेक्टर राबिन त्यागी की टीम को सूचना मिली थी कि बुराड़ी की एक जघन्य हत्या में शामिल चंदन कुमार, बिहार में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने 29 मई बिहार पहुंचकर उसे लखीसराय से गिरफ्तार कर लिया।

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता पर ब्रेक! इजराइल के लेबनान अभियान से भड़का तेहरान

● अमेरिका के साथ ईरान की शांति वार्ता इजरायल के लेबनान सैन्य अभियान के कारण स्थगित हो गई है।

जिससे पहले से ही नाजुक अमेरिका-ईरान युद्धविराम ढांचे पर गहरा दबाव पड़ा है। ईरान ने स्पष्ट किया है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

खबरों के मुताबिक, ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता स्थगित कर दी है। यह कदम वाशिंगटन और तेहरान के बीच पहले से ही नाजुक युद्धविराम ढांचे पर और अधिक दबाव डाल सकता है। यह घटनाक्रम लेबनान में इजरायल के चल रहे सैन्य अभियान के कारण बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच आया है। ईरान की समाचार एजेंसी तसनीम, जिसे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के करीबी माना जाता है, के अनुसार, तेहरान ने फिलहाल बातचीत रोकने का फैसला किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह विराम तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की चिंताओं और क्षेत्र में सहयोगी समूहों के हितों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता।

इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने चेतावनी दी थी कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ युद्धविराम समझौता लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लागू होता है, और कहा कि किसी भी क्षेत्र में उल्लंघन को पूरे युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा। X पर एक पोस्ट में, अराघची ने कहा कि युद्धविराम की शर्तें स्पष्ट हैं और उन्होंने उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए अमेरिका और इज़राइल को जिम्मेदार ठहराया।

अराघची ने लिखा कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम स्पष्ट रूप से लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्धविराम है। उन्होंने आगे कहा कि एक मोर्चे पर इसका उल्लंघन सभी मोर्चों पर युद्धविराम का उल्लंघन है। किसी भी उल्लंघन के परिणामों के लिए अमेरिका और इज़राइल ज़िम्मेदार हैं। ये टिप्पणियाँ इस बात पर जारी असहमति के बीच आई हैं कि क्या लेबनान को औपचारिक रूप से अमेरिका-ईरान युद्धविराम ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए। ईरान ने बार-बार यह तर्क दिया है कि किसी भी समझौते में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए और ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह समूह के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियानों को रोकना भी अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले ही संकेत दिया है कि युद्धविराम मुख्य रूप से ईरान से जुड़े प्रत्यक्ष संघर्षों पर लागू होता है और लेबनान में चल रहे अभियानों पर स्वतः लागू नहीं होता।

देश के शीर्ष 200 संस्थानों में असम विश्वविद्यालय, एनपीटीईएल- स्वयं में हासिल की 'एए रेटिंग'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: सिलचर, गत 31 मई। ऑनलाइन शिक्षा मंच एनपीटीईएल (NPTEL) के स्वयं (SWAYAM) कार्यक्रम में असम विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए वर्ष 2026 के जनवरी-जून सत्र में देश के शीर्ष 200 संस्थानों की सूची में स्थान बनाया है। विश्वविद्यालय के एनपीटीईएल-स्वयं लोकल चैप्टर को इस उपलब्धि के लिए 'एए रेटिंग' प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2017 में एनपीटीईएल लोकल चैप्टर की स्थापना के बाद यह पहला अवसर है जब असम विश्वविद्यालय ने यह प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। उत्तर-पूर्व भारत के शैक्षणिक संस्थानों में इससे पहले केवल नेरिस्ट (North Eastern Regional Institute of Science and Technology) और तेजपुर विश्वविद्यालय ही शीर्ष 200 संस्थानों की सूची में शामिल हो सके थे। नेरिस्ट ने वर्ष 2024 और 2025 में तथा तेजपुर विश्वविद्यालय ने वर्ष 2025 और 2026 में यह उपलब्धि हासिल की थी।

स्वयं-एनपीटीईएल लोकल चैप्टर के समन्वयक प्रदीसो दास ने इस सफलता का श्रेय कुलपति प्रो. राजीव मोहन पंत तथा आईक्यूएसी निदेशक प्रो. पीयूष पांडेय के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग को दिया। उन्होंने विभिन्न विभागाध्यक्षों और संकाय अधिष्ठाताओं (डीन) के योगदान की भी सराहना की। शिक्षा जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि इस उपलब्धि से राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में असम विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और सुदृढ़ होगी। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी तथा एनपीटीईएल पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण विश्वविद्यालय को यह सम्मानजनक मान्यता प्राप्त हुई है।

गर्मी के टॉर्चर के बीच 'कूल' खबर, दिल्ली में अब फ्री मिलेगा साफ और ठंडा पानी

नई दिल्ली। भीषण गर्मी को देखते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (NDMC) ने नागरिकों को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब NDMC क्षेत्र के सभी 38 वाटर एटीएमों पर 2 जून 2026 से पेयजल पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। NDMC उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने सोमवार को विभिन्न स्थानों पर वाटर एटीएमों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मशीनों की कार्यक्षमता, स्वच्छता और पानी की गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद चहल ने कहा कि बढ़ते तापमान में राहगीरों, मजदूरों, पर्यटकों और विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं शीतल पानी उपलब्ध कराना NDMC की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 23 वाटर एटीएम पर 300 मिलीलीटर पानी ?1 में मिलता था, जबकि 15 पहले से ही निःशुल्क थे। अब सभी 38 मशीनें फ्री सेवा देंगी। NDMC ने वर्ष 2018-19 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाटर एटीएम परियोजना शुरू की थी। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर चल रही थी।

दिनदहाड़े गाय चोरी: ग्रामीणों ने दो आरोपियों को पकड़ा, दो फरार; पुलिस ने वाहन बरामद किया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: श्रीभूमि जिले के निविया क्षेत्र के निकट लालछड़ा बागान क्षेत्र में दिनदहाड़े गाय चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, 1 जून सोमवार दोपहर स-11श्र-7799 नंबर की एक ऑल्टो कार में सवार चालक सहित चार युवकों का एक समूह दुल्लभछड़ा-भेटारबंद मार्ग से लालछड़ा चाय बागान क्षेत्र में पहुंचा। आरोपियों ने नाचघर के सामने वाहन रोककर कुछ देर तक आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने वहां बंधी एक गाय की रस्सी खोलकर उसे वाहन में लाद लिया। घटना को दूर से देख रहे स्थानीय युवकों ने शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी वाहन लेकर नीविया की ओर तेज गति से भाग निकले।

सूचना फैलते ही विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी लगातार मार्ग बदलकर भागते रहे। मोटरसाइकिल से पीछा करने के बावजूद वे पकड़ में नहीं आ सके। आरोपी मगाराछड़ा, पठाखाउरी और हाथीडिपु फॉरेस्ट मार्ग से होते हुए सिंगला बागान क्षेत्र तक पहुंचे। वहां ग्रामीणों ने सड़क पर अवरोध लगाने की कोशिश की, लेकिन वाहन नहीं रुका। हालांकि, घिरते देख आरोपियों ने सिंगला बागान के एक सुनसान इलाके में गाय को उतार दिया और दुल्लभछड़ा फॉरेस्ट बीट कार्यालय के पास सिंगला नदी क्षेत्र में वाहन छोड़कर फरार हो गए।

बाद में स्थानीय लोगों ने दबिश देकर दो

संदिग्धों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि दो अन्य आरोपी फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने वाहन को सिंगला नदी क्षेत्र से बरामद कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की पहचान कर जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा।

दक्षिणी जिला पुलिस को बड़ी सफलता, 100 से अधिक वाहन चोरी की वारदातों में शामिल शातिर ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दक्षिणी जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (एएटीएस) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 100 से अधिक वाहन चोरी की वारदातों में शामिल एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस तथा चोरी की गई नौ मोटरसाइकिल और स्कूटर बरामद किए गए हैं।गिरफ्तार आरोपी की पहचान सूरज कुमार उर्फ मन्नीकांत उर्फ मणि (30 वर्ष) निवासी जिला बांका, बिहार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ वाहन चोरी, लूटपाट, झपटमारी, चोरी का सामान रखने तथा आर्म्स एक्ट से जुड़े 51 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं पुलिस अधिकारियों के अनुसार दक्षिणी जिले में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं की जांच के दौरान विभिन्न घटनास्थलों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच में एक ही व्यक्ति कई वारदातों में दिखाई दिया। तकनीकी निगरानी, स्थानीय सूचना तंत्र और गुप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह नवंबर 2025 में जेल से बाहर आने के बाद फिर से वाहन चोरी की वारदातों में सक्रिय हो गया था। वह लगभग रोजाना मोटरसाइकिल और स्कूटर चोरी कर उन्हें हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बेच देता था।पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई नौ मोटरसाइकिल एवं स्कूटर बरामद किए हैं। इसके अलावा उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी से वाहन चोरी के कुल 14 मामलों का खुलासा हुआ है, जिनमें दिल्ली के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज मामले शामिल हैं।जांच के दौरान आरोपी ने यह भी बताया कि वह चोरी के वाहनों को मेवात निवासी राशिद नामक व्यक्ति के माध्यम से ठिकाने लगाता था। पुलिस ने इस रिसीवर की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे वाहन चोरी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। इस कार्रवाई को एएटीएस दक्षिणी जिला की टीम ने इंस्पेक्टर उमेश यादव के नेतृत्व तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन) अरविंद कुमार की निगरानी में अंजाम दिया। टीम में एसआई नवदीप, एएसआई देशराज, एचसी राजकुमार, एचसी संदीप, एचसी रघुवेंद्र, एचसी अमित, कांस्टेबल अरविंद, कांस्टेबल मंदिर और कांस्टेबल हरीश शामिल रहे।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अनंत मित्तल ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी और चोरी के वाहनों की बरामदगी दक्षिणी जिला पुलिस की तकनीकी जांच, खुफिया तंत्र और सतत निगरानी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वाहन चोरी और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस वाहन चोरी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।

घरेलू हिंसा केस में विधायक राजा भैया को दिल्ली HC से झटका, कहा- समन सही; अब क्या कोर्ट में पेश होना होगा?

» दिल्ली हाई कोर्ट ने राजा भैया के समन को सही ठहराया

» घरेलू हिंसा मामले में पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने केस किया

» विशेष अदालत को सुनवाई का अधिकार, हाई कोर्ट ने कहा

नई दिल्ली। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ऊर्फ राजा भैया के खिलाफ पत्नी भानवी कुमारी सिंह द्वारा दायर घरेलू हिंसा के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया है।

हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू की सांसद-विधायक के लिए तय कोर्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत एक सक्षम मजिस्ट्रेट कोर्ट बनी रहेगी और मौजूदा विधायकों के विरुद्ध चल रही सुनवाई कर सकती है। रघुराज प्रताप सिंह ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि सांसदों/विधायकों के लिए नामित विशेष अदालत के पास घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत दायर इस मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय में उपस्थिति एवं फोन चालू रखने के आदेश पर शिक्षकों में रोष, आदेश वापस लेने की मांग तेज

● परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ, बिहार प्रदेश ने शिक्षा मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को भेजा मांग पत्र।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पटना। शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मावकाश अवधि में शिक्षकों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने एवं मोबाइल फोन चालू रखने संबंधी जारी निर्देश के खिलाफ शिक्षकों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ, बिहार प्रदेश ने शिक्षा मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर उक्त आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर ने कहा कि जब विभाग ने पूर्व निर्धारित अवकाश तालिका के अनुसार ग्रीष्मावकाश घोषित किया है, तो उसी अवधि में शिक्षकों को मुख्यालय में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना विरोधाभासी एवं अव्यावहारिक है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि शिक्षकों को अवकाश का वास्तविक लाभ ही नहीं मिलना है, तो फिर ग्रीष्मावकाश घोषित करने का औचित्य क्या है?

महासंघ ने अपने पत्र में कहा है कि ग्रीष्मावकाश की तिथियां पहले से निर्धारित रहती हैं और अधिकांश शिक्षक इस अवधि में अपने परिवार के साथ समय बिताने, सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन तथा मानसिक एवं शारीरिक पुनर्स्थापन की योजनाएं बनाते हैं। ऐसे में अचानक जारी आदेश शिक्षकों के वैध अधिकारों एवं व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप के समान है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षक पूरे वर्ष शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ करते हैं। ग्रीष्मावकाश उनके लिए विश्राम और परिवार के साथ समय बिताने का एकमात्र अवसर होता है। अवकाश अवधि में मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश शिक्षकों के मनोबल को प्रभावित करने वाला है।

परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने विभाग से शिक्षकों की भावनाओं एवं व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आदेश को अविलंब वापस लेने की मांग की है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो संगठन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार की होगी। महासंघ ने अपने पत्र के अंत में यह भी कहा है कि 'यदि ग्रीष्मावकाश वास्तव में अवकाश है तो शिक्षकों को उसका लाभ मिलना चाहिए, और यदि मुख्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है तो फिर अवकाश घोषित करने का औचित्य क्या है?

पढ़ाई के साथ ऑटो चलाकर परिवार का सहारा बनी असम की छात्रा, बनी प्रेरणा

● असम की छात्रा संघर्ष और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी अनामिका चौधरी।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि असम श्रीभूमि जिले के श्रीकोना क्षेत्र की रहने वाली अनामिका चौधरी पूर्वोत्तर भारत से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहाँ एक युवा छात्रा शिक्षा के साथ-साथ अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी संभाल रही है। अनामिका चौधरी वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और साथ ही ऑटो-रिक्शा चलाकर अपने परिवार के भरण-पोषण में सहायता कर रही हैं।

श्रीभूमि जिले के श्रीकोना क्षेत्र की रहने वाली अनामिका सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपने अध्ययन को लगातार जारी रखे हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, वह दिन में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हैं और खाली समय में ऑटो चलाकर आय अर्जित करती हैं। उनका यह संघर्षपूर्ण जीवन अब स्थानीय स्तर से आगे बढ़कर एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने यह साबित किया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु

» असम की छात्रा पढ़ाई के साथ ऑटो चला रही हैं

» परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी निभा रही हैं

» शारीरिक श्रम और शिक्षा का संतुलन बना रही हैं

» स्थानीय लोगों के लिए बनी प्रेरणा

» पढ़ाई के साथ ऑटो चलाकर परिवार का सहारा बनी असम की छात्रा

» संघर्ष और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी अनामिका चौधरी

» किताबों के साथ सड़क पर मेहनत, प्रेरणा बनी युवा छात्रा।

विवाहिता की मौत पर बवाल, सड़क जाम के बाद पति गिरफ्तार

● तीसरे दिन दोपहर बाद विवाहित महिला का किया अंतिम संस्कार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिंगाही-खीरी। फरदहिया गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने सोमवार को बड़ा रूप ले लिया। परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी पति की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर शव सड़क पर रखकर धरना-प्रदर्शन किया। कई घंटों तक चले हंगामे और सड़क जाम के बाद पुलिस ने हत्या व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद करीब तीसरे दिन दोपहर बाद विवाहिता का अंतिम संस्कार कराया गया। जानकारी के अनुसार, फरदहिया गांव निवासी बबिता देवी (22) का विवाह करीब एक वर्ष पूर्व धौरहरा क्षेत्र के राजापुर निवासी लवकुमार के साथ हुआ था। परिजनों के मुताबिक बबिता गुरुवार को मायके आई थी और शुक्रवार को उसका पति भी ससुराल पहुंच गया था। शनिवार सुबह गांव के बाहर खेत में बने एक बंगले में बबिता का शव फंदे से लटका मिला।

मृतका की मां और बाबा ने आरोप लगाया कि पति ने बबिता की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने घर पर शव रखकर धरना शुरू कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी तथा दहेज हत्या की धाराएं बढ़ाने की मांग करने लगे। सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी निघासन शिवम कुमार और थाना प्रभारी दिलीप कुमार चौबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजन कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए।

सोमवार को मामला और गरमा गया। परिजनों व ग्रामीणों ने सिंगाही-नौबना मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। हालात बिगड़ते देख निघासन, तिकुनियां और पढुआ सर्किल की पुलिस भी मौके पर बुला ली गई। काफी समझाने-बुझाने के बावजूद परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। स्थिति गंभीर होने पर अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिजनों से वार्ता कर निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ निघासन शिवम कुमार के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने देर रात आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। पुलिस की मौजूदगी में विवाहिता का अंतिम संस्कार कराया गया। सीओ निघासन शिवम कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की पुलिस तैनात रही।

अम्बेडकर नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18.752 किलोग्राम गांजा के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। दक्षिणी जिला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अम्बेडकर नगर थाना पुलिस की इस कार्रवाई में कुल 18.752 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से अंतरराज्यीय स्तर पर संचालित एक नशा आपूर्ति नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा उजागर हुआ है।पुलिस के अनुसार, 29 मई को मदनगीर क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान थाना अम्बेडकर नगर की टीम ने बीआरटी रोड स्थित चौहान स्वीट्स के पास एक महिला को संदिग्ध अवस्था में बैग लेकर घूमते देखा। पुलिस द्वारा की गई जांच में उसके बैग से गांजा के दो पैकेट बरामद हुए। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार महिला की पहचान निशा (38) निवासी डाबड़ी एक्सटेंशन के रूप में हुई। पूछताछ और मोबाइल फोन की तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस को नशा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गौतम (19) को मोती नगर के सुदर्शन पार्क क्षेत्र से तथा नरेश (35) को एक विशेष छापेमारी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में तीनों आरोपियों के कब्जे से कुल 18.752 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इनमें निशा से 4.129 किलोग्राम, गौतम से 9.623 किलोग्राम तथा नरेश से 4.742 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।जांच के दौरान यह भी सामने आया कि नरेश के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि निशा एक आबकारी अधिनियम के मामले में शामिल रह चुकी है। गौतम के खिलाफ फिलहाल कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है।इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में एसआई रामफूल, एचसी राजकुमार, एचसी अशोक, कांस्टेबल संजय, कांस्टेबल श्रीराम और महिला कांस्टेबल कामिनी शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों ने टीम की सतर्कता, तकनीकी निगरानी और पेशेवर जांच की सराहना की है।दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अनंत मित्तल ने बताया कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और पूरे सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।